भोपाल | शुक्रवार | 28 नवंबर 2025 | वर्ष 69 | अंक 294 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

भोपाल 70 वां वर्ष संस्करण

4 वोटों के लिए न निकालें बोतल से बाबरी का जिन्न

5 परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलेंगे

8 किदांबी श्रीकांत की एकतरफा धमाकेदार जीत

9 देश का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल हुआ लॉन्च

विनजो गेम्स के निदेशक गिरफ्तार

505 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त | **2002** निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई | **10** राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की

नई दिल्ली ,27 नवम्बर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार देर रात विनजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को गिरफ्तार कर लिया. दोनों अधिकारियों को बेंगलुरु में एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया. अदालत ने निर्देश दिया है कि रिमांड एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए दोनों को गुरुवार सुबह 11.30 बजे फिर से पेश किया जाए.

यह कार्रवाई ईडी द्वारा हाल ही में किए गए कई अभियानों की कड़ी में की गई है. 18 से 22 नवंबर 2025 के बीच ईडी की बेंगलुरु जोनल टीम ने दिल्ली और गुरुग्राम में चार ठिकानों पर छापे मारे. धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई इस छापेमारी में एजेंसी ने विनजो गेम्स से जुड़े बैंक खातों, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में रखी लगभग 505 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की. जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी पर उपभोक्ताओं के बैंक खाते ब्लॉक करने, फर्जी पहचान बनाने, पैन का दुरुपयोग और केवाईसी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप हैं.

उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके नाम पर अवैध लेन-देन किए गए. साथ ही, सरकार द्वारा 22 अगस्त 2025 से रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध के बावजूद कंपनी ने करीब 43 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं को वापस नहीं किए.

मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड: ईडी की देशव्यापी छापेमारी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में भ्रष्टाचार से जुड़े एक बड़े मामले में बुधवार देर रात को देशभर के 10 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की . यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में एक साथ की गई. मामला सीबीआई की उस प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें आरोप है कि मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी के बदले एनएमसी के कुछ अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने रिश्वत ली. इसके बदले कॉलेजों को मानकों में हेरफेर करने और शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दिलाई गई. ईडी ने जिन परिसरों पर तलाशी ली, उनमें विभिन्न राज्यों के सात मेडिकल कॉलेजों के कैंपस और मामले में आरोपी निजी व्यक्तियों के ठिकाने शामिल हैं. एजेंसी को छापों के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिलने की उम्मीद है, जो घोटाले की परतें खोल सकते हैं.

इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर ईडी की रेड

अकाउंट सेक्शन सील, मान्यता घोटाले की परतें फिर खुलीं

इंदौर। मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले की धनशोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पर छापा मारकर अकाउंट सेक्शन को सील कर दिया। ईडी टीम सुबह से परिसर में मौजूद रही और सभी वित्तीय रिकॉर्ड कब्जे में लेकर उनकी गहन जांच शुरू की गई। सूत्रों के अनुसार ईडी को कॉलेज के वित्तीय लेन-देन और मान्यता प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। इसी कॉलेज की मान्यता को लेकर पहले भी सीबीआई ने जांच में पाया था कि निरीक्षण प्रभावित करने के लिए रसूख और पैसों का इस्तेमाल हुआ था, जिसके चलते तीन डॉक्टरों सहित छह लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हवाला मार्ग से बड़े लेन-देन और दलालों के नेटवर्क की भूमिका भी सामने आई थी। ईडी ने इसी केस से जुड़े प्रमाण जुटाने के लिए देशभर में लगभग 15 स्थानों पर भी सर्च की है। टीम देर शाम तक कॉलेज में मौजूद रहकर दस्तावेजों की जांच करती रही।

किसानों को 238 करोड़ मुआवजा

- सीएम डॉ. मोहन यादव ने क्षतिग्रस्त फसलों की भरपाई के लिए दी राशि
- सिंगल क्लिक से 6 जिलों के 3.05 लाख किसानों को हुआ फायदा

श्योपुर,27 नवम्बर . मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील में आयोजित विशाल जनसभा में 6 जिलों के किसानों को फसल क्षति मुआवजा राशि का सिंगल क्लिक से वितरण किया. बड़ौदा थाने के समीप ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में कुल 3,05,410 प्रभावित किसानों के खातों में 238 करोड़ 78 लाख रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए. यह मुआवजा अतिवृष्टि, बाढ़ और पीला मौजेक कीट व्याधि से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई के तौर पर दिया गया.

इस वितरण में श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा जिलों की 23 तहसीलों के 2,148 ग्राम शामिल रहे. अकेले श्योपुर जिले के 1,03,078 धान उत्पादक किसानों को 100 करोड़ 83 लाख रुपये की राहत राशि मिली. अतिवृष्टि और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित श्योपुर में व्यापक नुकसान के बाद यह राहत किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई. इसके अलावा हरदा जिले के 95,989 किसानों को सोयाबीन क्षति हेतु 71 करोड़ 52 लाख रुपये, विदिशा के 51,830 किसानों को सोयाबीन व उड़द फसल हानि पर 29 करोड़ 15 लाख रुपये, नर्मदापुरम के 22,779 किसानों को 19 करोड़ 84 लाख रुपये, धार के 19,173 किसानों को सोयाबीन और मक्का क्षति पर 10 करोड़ 31 लाख रुपये, खंडवा के 12,961 किसानों को पीला मौजेक कीट से प्रभावित सोयाबीन फसल के लिए 7 करोड़ 13 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया.

लोकार्पण व शिलान्यास के साथ विकास को नई गति

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत सेसईपुरा में 2.75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आदिवासी बालक आश्रम का लोकार्पण किया गया. साथ ही- श्योपुर में 14.80 करोड़ रुपये की लागत से नर्सिंग कॉलेज भवन, 14.95 करोड़ रुपये से 50 बिस्तरीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय, 96 लाख रुपये से बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण ज्ञान प्रसार केंद्र, ग्राम लहरौनी (2.61 करोड़), बलावनी (2.53 करोड़) और डाबीपुरा (2.49 करोड़) में नवीन 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण का शिलान्यास किया गया.

एक नजर में

डीजीपी-आईजीपी को संबोधित करेंगे मोदी

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी शनिवार और रविवार को रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित होने वाले पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे. तीन दिवसीय यह सम्मेलन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर व्यापक विमर्श होगा. 'विकसित भारत-सुरक्षा आयाम' विषय पर आधारित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद-रोधी रणनीतियां, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा, तथा पुलिस व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और फोरेंसिक विज्ञान के बढ़ते उपयोग पर विशेष चर्चा की जाएगी.

एनसीआर प्रदूषण पर सुको ने जतायी चिंता

नयी दिल्ली. न्यायालय ने आगाह किया कि न्यायपालिका से इस स्तर के संकट का तुरंत समाधान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरूवार को इस मामले की तत्काल सूचीबद्धता के उल्लेख की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता एक स्वास्थ्य आपातकाल है. प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को उजागर करने वाली न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह से मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम समस्या जानते हैं.

गुस्ताखी माफ

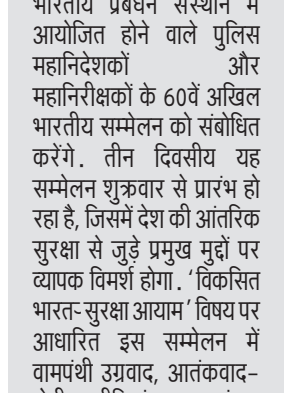

सोशल मीडिया कंटेंट पर सुको सख्त

नई दिल्ली, 27 नवम्बर. सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ते आपत्तिजनक एवं एडल्ट कंटेंट को लेकर गुरुवार को दो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की. अदालत ने साफ कहा कि ऑनलाइन डाले जाने वाले अशोभनीय कंटेंट की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी और केंद्र सरकार को ऐसे मामलों के लिए एससी / एसटी एक्ट जैसी कठोर व्यवस्था चार सप्ताह में तैयार करनी चाहिए.

पीठ ने टिप्पणी की कि जब तक किसी गंदे या अनुचित कंटेंट को हटाया जाता है, तब तक लाखों लोग उसे देख चुके होते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल अश्लीलता का नहीं, बल्कि बोलने की आज़ादी के दुरुपयोग और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है. कई लोग अभद्र कंटेंट बनाकर पैसे कमा रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी तय करने का कोई तंत्र नहीं है.

केंद्र को 4 हफ्ते में नियम बनाने के दिए निर्देश

अशोभनीय कंटेंट की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी

न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे कंटेंट पर स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए जो केवल 18+ दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हो जो इसे देख सकता है. अदालत ने सुझाव दिया कि कंटेंट शुरू होने से पहले आधार आधारित उम्र-प्रमाणन अनिवार्य किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नाबालिग आपत्तिजनक सामग्री तक न पहुंचें.

आईएएस वर्मा को बर्खास्त करे सरकार

रोशनपुरा चौराहे पर ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 27 नवंबर. मोहन सरकार से आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया गया. गुरूवार को देर शाम बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने वर्मा के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध किया. प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस ने इस मौके पर समाज के कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया, जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया. विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी रही.

ब्राह्मण समाज के बैनर तले हुए प्रदर्शन के बीच आईएएस वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. प्रदर्शन के दौरान सुधीर नायक, नगर निगम भोपाल के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्र, पुष्पेंद्र मिश्रा और कर्मचारी नेता श्यामसुंदर शर्मा सहित समाज के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

एकजुट हुए लोगों ने कहा कि वर्मा ने ब्राह्मण समाज महिलाओं और बेटियों को लेकर जो टिप्पणी की है, उसे माफ नहीं किया जाएगा. लोगों ने वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शासकीय सेवा से उनको बर्खास्त करने की मांग की. आईएएस वर्मा को लेकर समाज के लोगों ने इस मौके पर कहा कि वर्मा इससे पहले भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सरकार ने जल्द ही बडा एक्शन नहीं लिया, तो प्रदेश स्तर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

चुनौतियों से निपटने सेना में बदलाव की जरूरत

नयी दिल्ली 27 नवम्बर . सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि तेजी से बदलते और अनिश्चित वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना में बड़े स्तर पर बदलाव किये जाने की जरूरत है.

जनरल द्विवेदी ने कहा यहां सेना के सेमिनार चाणक्य डिफेंस डायलॉग - 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, जहां बड़ी ताकतें लगातार टकरा रही हैं और प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. उन्होंने कहा, दुनिया शीत युद्ध की द्विध्रुवीयता से संक्षिप्त एकध्रुवीय दौर के बाद अब एक अनिश्चित और बिखरी हुई व्यवस्था की ओर अग्रसर है. अभी दुनिया भर में 50 से अधिक संघर्ष चल रहे हैं और यह कहना कि हम अशांत समय में जी रहे हैं, शायद हल्की टिप्पणी होगी.

उन्होंने कहा कि वैश्विक भू-राजनीति प्रतिरोधक क्षमता, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध तैयारियों में जुटी है और ऐसे में सेना के समक्ष एक मूलभूत प्रश्न उठता है कि उसे किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत किस तरह के बदलावों की जरूरत है. उन्होंने इस बारे में एक दीर्घकालिक रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सेना का एकीकरण और इसे प्रौद्योगिकी से लैस करना है.

सेना प्रमुख ने कहा कि सेना में व्यापक बदलावों के तहत आत्मनिर्भरता, त्वरित नवाचार, अनुकूलन और पारिस्थितिकी तंत्र सुधार और सैन्य-नागरिक समन्वय पर जोर दिये जाने की जरूरत है. उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में गहन तालमेल की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि युद्धक क्षमता का विकास बहु-एजेंसी और बहु-आयामी प्रयास होना चाहिए.

आदिल के व्हाट्सऐप चैट किए रिकवर

- दिल्ली कार ब्लास्ट में हुआ बड़ा खुलासा
- टेरर फंडिंग की नई कड़ियाँ आईं सामने

नई दिल्ली,27 नवम्बर . दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जांच के साथ-साथ चौंकाने वाले खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई ने खुलासा किया है कि जैश-ए-मोहम्मद की लेडी कमांडर डॉ. शाहीन शाहिद उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि पत्नी है. अब तक दोनों के प्रेम संबंधों की बात सामने आती रही थी, लेकिन मुजम्मिल के इस स्वीकारोक्ति ने जांच को नई दिशा दे दी है.

इसी बीच एजेंसियों ने लाल किला विस्फोट मामले में बड़ा तकनीकी ब्रेकथ्रू हासिल किया है. मुख्य आरोपी डॉ. आदिल के फोन से डिलीट किए गए व्हाट्सऐप चैट रिकवर कर लिए गए हैं. इन संदेशों में उसकी लगातार पैसों की मांग और आर्थिक तंगी का उल्लेख है. संदेह है कि यही रकम 10 नवंबर के हमले में खर्च हुई. सूत्रों के अनुसार कुल 26 लाख रुपये में से 8 लाख रुपये आदिल ने उपलब्ध कराए थे. ग्रुप चैट में उसे 'खजांची' के नाम से पुकारा जाता था.

बिहार हार | कांग्रेसी रणनीतिकारों ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं व पार्टी के 61 उम्मीदवारों से हुई चर्चा

समीक्षा बैठक में बहुपक्षीय तर्कों व आरोपों पर हुआ मंथन

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली,27 नवंबर.बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के कारण व कारकों को ढूंढने में जुटे कांग्रेसी रणनीतिकारों ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं व पार्टी के 61 उम्मीदवारों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की है.

सूत्रों की मानें तो पार्टी के केन्द्रीय वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आरंभ हुई बैठक का एजेंडा पहले से ही तय कर दिया गया था. सभी उम्मीदवारों को अपने शब्दों में हार के प्रमुख कारणों का विवरण देने को कहा गया था. इतना ही नहीं जिम्मेदार प्रभारी सचिवों को भी एक रिपोर्ट देने को कहा गया था. प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक दल के नेता से भी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से लेकर प्रचार अभियान तक के बिंदुवार व विस्तृत जानकारी मांगी गई थी. यानी पार्टी रणनीतिकार किसी भी परिणाम पर पहुंचने के पहले बहुपक्षीय रिपोर्ट को प्राप्त करना चाहते हैं. सूत्रों की मानें तो इस बैठक में वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, अखिलेश प्रसाद सिंह व निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से भी हार के प्रमुख कारणों पर विमर्श किया गया है. उम्मीदवारों के घोषणा के बाद जिस तरह से तारिक अनवर ने प्रदेश संगठन, प्रभारी महासचिव कृष्णा अल्लावरू, तीनों प्रभारी सचिवों व वार रूम प्रभारी के निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्हें कठघरे में खड़ा किया था, उस संदर्भ में भी उनसे रिपोर्ट मांगी गई. इसके अलावा कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी पदाधिकारियों पर टिकट बेचने के आरोपों के संदर्भ में भी व्यक्तिगत चर्चा की गई है. हालांकि इस बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता की मानें तो समीक्षा की प्रक्रिया सिर्फ खानापूर्ति जैसा प्रतीत हो रही थी. उनका कहना है कि जिन पर आरोप है उनसे ही रिपोर्ट ली जाएगी तो सच्चाई कैसे सामने आएगी ? जो उम्मीदवार ऐन केन प्रकारेण यानी किसी भी तरह से उम्मीदवारी पाने में सफल रहे हैं वे कैसे अपने ही चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे ? ऐसे में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी रणनीतिकारों के सामने उम्मीदवार चयन की आरंभिक प्रक्रिया से लेकर अंत तक की पारदर्शी रिपोर्ट प्रभारी महासचिव व प्रदेश अध्यक्ष से मांगने का सुझाव दिया है. इसके अलावा समीक्षा की अगली कड़ी में नाराज पक्ष से भी बात करने और उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले तथ्यात्मक साक्ष्यों पर भी विचार करने का सुझाव दिया गया है.

सूत्रों की मानें तो आरंभिक बैठक में कुछ नेताओं द्वारा यह प्रयास किया गया कि हार का ठीकरा चुनाव के समय सरकार द्वारा महिला मतदाताओं को दस हजार रूपए दिए जाने, ईवीएम में गड़बड़ी, अंकगणितिय फार्मूला, अंत समय तक राजद व सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की अनिश्चितता, गठबंधन के प्रचार अभियान में एकजुटता का अभाव पर फोड़ा जाए. लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उक्त तर्कों के सहारे सुनियोजित तरीके से जिम्मेदार लोगों द्वारा आरोप मुक्त होने के प्रयास पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए गए जिसके बाद भविष्य में कुछ और बैठक करने की बात के साथ सभी 61 उम्मीदवारों को बुथस्तरीय रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द सौंपने का निर्देश दिया गया है.

यूपीएससी ने सौ वर्षों के सफर में विशिष्ट पहचान बनायी : डॉ. मिश्रा

नयी दिल्ली 27 नवम्बर . प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ.पीके मिश्रा ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले सौ वर्षों में योग्यता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को बनाए रखते हुए देश के सबसे सम्मानित संस्थानों में अपनी पहचान बनाई है.

डा.मिश्रा ने गुरुवार को आयोग के शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसे संविधान के निर्माताओं की दूरदृष्टि और उन मार्गदर्शकों को श्रद्धांजलि बताया जिन्होंने आयोग को उसके प्रारंभिक वर्षों में दिशा दी. उन्होंने कहा कि संस्थान ने पिछले वर्षों में योग्यता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को बनाए रखते हुए सम्मानित संस्थानों में अपनी जगह बनाई है. उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्षों, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने चुनौतियों के बावजूद संस्थान की निष्पक्षता और योग्यता के सिद्धांतों को बरकरार रखा है. उन्होंने आयोग की लंबी यात्रा, इसके पूर्ववर्ती आयोग और सिविल सेवाओं की बदलती भूमिका का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं की जिम्मेदारियां समय के साथ कानून-व्यवस्था से विकास, प्रौद्योगिकी, जलवायु चुनौतियों और आपदा प्रबंधन तक विस्तृत हुई हैं.